PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 024
दि. 24.05.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र; पीएम मोदी बोले- 'विकसित भारत' के अहम सारथी हैं हमारे युवा

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 19वें रोजगार मेले में अलग-अलग सरकारी विभागों और संगठनों में 51 हजार से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि भारत के युवा 'विकसित भारत' की ओर बढ़ रही यात्रा को गति देने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'रोजगार मेला' युवाओं को नए अवसर प्रदान कर सशक्त बनाने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।'

उन्होंने कहा, 'अभी दो दिन पहले मैं पांच देशों की यात्रा करके लौटा हूं।

कहने को तो ये सिर्फ पांच देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुईं, विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है।'

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर एक्सपोजर भी मिले।

उन्होंने कहा, 'आज स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ विनिर्माण से जुड़े क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी साझेदारी एक नई अर्थव्यवस्था के नए अवसर के दरवाजे खोल रही हैं। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ 'ग्रीन ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी' में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्री में मजबूत करेगा।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग-अलग क्षेत्र में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं।(

पीएम मोदी ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को दी जन्मदिन की बधाई, उज्ज्वल भविष्य की कामना की

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्हें एक युवा और ऊजार्वान नेता बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके कार्यों में सेवा और राष्ट्र-निर्माण के आदर्शों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की झलक मिलती है। इस दौरान, पीएम मोदी ने उनके दीघार्यु और स्वस्थ जीवन की कामना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक युवा और ऊजार्वान नेता के रूप में उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकताओं को सशक्त करने के लिए स्वयं को पूर्ण समर्पण के साथ समर्पित किया है। उनकी सोच, ऊजार्वान नेतृत्व और संगठनात्मक कार्य व प्रशासन की गहरी समझ ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया है। उनका कार्य सेवा और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दशार्ता है। राष्ट्र की निरंतर सेवा के लिए मैं उनके दीघार्यु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नितिन नवीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने पोस्ट किया, 'भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सरल व्यक्तित्व, संगठन के प्रति समर्पण और कार्यकताओं में सेवा व कर्तव्य भाव को बढ़ावा देने का सतत प्रयास, पार्टी को और भी सशक्त बनाता रहेगा। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीघार्यु और सफल जीवन की कामना करता हूं।'

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नितिन नवीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'युवा और ऊजार्वान नेतृत्व के रूप में आपने कम समय में ही अपनी सक्रिय कार्यशैली, संगठनात्मक समझ और कार्यकताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता से सभी के बीच विशेष पहचान बनाई है। संगठन को मजबूत करने के प्रति आपका समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यंत सराहनीय है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीघार्यु की कामना करता हूं।'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, 'युवा ऊर्जा के प्रतीक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपके कुशल नेतृत्व में संगठन और सभी कर्मठ कार्यकताओं में 'राष्ट्र प्रथम' का भाव और सुदृढ़ हुआ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ व सुयशपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो।'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नितिन नवीन को बधाई देते हुए पोस्ट किया, 'आपकी दूरदर्शी सोच और समर्पित कार्यशैली से संगठन निरंतर सशक्त हो रहा है। आपका प्रेरणादायी मार्गदर्शन हम सभी कार्यकताओं को सदैव नई ऊर्जा, उत्साह और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है।

गर्मी का तांडव जारी, 46.4त्ड पहुंचा बांदा का तापमान, आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

देश के बड़े हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं, कई राज्यों में 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश सहित कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में लू की स्थिति लगातार बनी हुई है।

जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। IMD का इन राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने दक्षिणी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट बरकरार है।

यूपी में लाउडस्पीकर के जरिए भी दिया जाएगा मौसम का अलर्ट, सीएम योगी ने अफसरों को दिए कड़े निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम व आपदा को लेकर लाउडस्पीकर से भी अलर्ट जारी किया जाए। उन्होंने राज्य में मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सटीक, त्वरित व जनकेंद्रित बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि मौसम संबंधी अलर्ट के लिए एफएम रेडियो, मोबाइल अलर्ट व इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल किया जाए।

शनिवार को उन्होंने अपने सरकारी आवास पांच कालीदास मार्ग पर राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पिछली 13 मई को आए आंधी-तूफान की समीक्षा प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बताया कि आईएमडी के मल्टी-हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (एमएचईडब्ल्यूएस) द्वारा इस घटना की सात दिन पहले से निगरानी की जा रही थी।

प्रारंभ में येलो वार्निंग जारी की गई, जिसे बाद में ऑरेंज वॉर्निंग तथा कई जिलों में रेड अलर्ट में अपग्रेड किया गया और तेज आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार वाली हवाओं की आशंका जताई गई थी। कई स्थानों पर हवा की गति 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई।

भदोही, प्रयागराज, फतेहपुर, लखनऊ, मीरजापुर, रायबरेली, कानपुर नगर और उन्नाव सहित कई जिलों के लिए 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा चलने संबंधी नाउकास्ट अलर्ट जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री ने मौसम संबंधी पूर्व सूचना मिलने के बाद संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा लिया।

'माता-पिता आईएएस, फिर भी आरक्षण?' क्रीमी लेयर रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए तीखे सवाल, क्या है पूरा मामला

(जीएनएस)।

देश में आरक्षण व्यवस्था को लेकर दशकों से चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ऐसा सवाल उठाया है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।

अदालत ने पूछा है कि अगर किसी परिवार ने आरक्षण का लाभ लेकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पर्याप्त उन्नति कर ली है, तो क्या अगली पीढ़ी को भी उसी तरह आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए? सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की टिप्पणी-"अगर माता-पिता दोनों क्लास अधिकारी हैं, तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?"-अब इस बहस का केंद्र बन गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। लेकिन जब कोई परिवार शिक्षा, नौकरी और आर्थिक स्थिति में काफी आगे बढ़ चुका हो, तब अगली पीढ़ी को भी वही लाभ देना न्यायसंगत है या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। ऐसे में यदि हर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेती रहेगी, तो यह व्यवस्था कभी अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएगी।

यह मामला कर्नाटक के कुरुबा समुदाय से जुड़े एक उम्मीदवार का है, जिसे ओबीसी श्रेणी के तहत सहायक अभियंता पद पर चयन मिला था। हालांकि जिला जाति एवं आय सत्यापन समिति ने उसे 'क्रीमी लेयर' में मानते हुए जाति वैधता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया।

समिति ने पाया कि उम्मीदवार के माता-पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और परिवार की वार्षिक आय करीब 19.48 लाख रुपये है, जो निर्धारित सीमा से अधिक है। इसी आधार पर उसे आरक्षण लाभ के लिए अयोग्य माना गया।

उम्मीदवार की ओर से पेश अधिवक्ता शशांक रत्नू ने अदालत में दलील दी कि केवल वेतन आय के आधार पर किसी को क्रीमी लेयर नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों में सरकारी कर्मचारियों की स्थिति-जैसे वे ग्रुप 'अ' या 'इ' सेवा में हैं-ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केवल वेतन आय को आधार बनाया गया, तो महंगाई और वेतन संरचना के कारण चपरासी, ड्राइवर और क्लर्क जैसे निचले स्तर के कर्मचारी भी आरक्षण से बाहर हो सकते हैं, जबकि वे सामाजिक रूप से अब भी पिछड़े हो सकते हैं।

'सामाजिक उन्नति के बाद भी क्यों चाहिए आरक्षण?'

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए कि आर्थिक और शैक्षिक उन्नति का सामाजिक स्थिति पर असर पड़ता है। अदालत ने कहा कि यदि माता-पिता पहले ही आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पदों और बेहतर जीवन स्तर तक पहुंच चुके हैं, तो अगली पीढ़ी को उसी आधार पर लगातार लाभ देना पुनर्विचार का विषय है। पीठ ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में संतुलन जरूरी है, ताकि इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद और अब भी पिछड़े वर्गों तक पहुंच सके।

SC/ST में भी क्रीमी लेयर पर बहस तेज

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट में एससी/एसटी वर्गों के भीतर भी 'क्रीमी लेयर' लागू करने को लेकर बहस तेज हो चुकी है। अगस्त 2024 में सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की थी।

श्रमिकों का सम्मान और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथ

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें सम्मान तथा सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को अधिक प्रभावी तथा व्यापक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 'बाल श्रमिक विद्या योजना' को प्रदेश के सभी 75 जिलों तक विस्तार देने, 'सेवामित्र व्यवस्था' को और मजबूत बनाने, बड़े शहरों में निर्माण श्रमिकों के लिए आधुनिक सुविधा केंद्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के निर्देश दिए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास की सबसे बड़ी ताकत हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही निजी क्षेत्र के सहयोग से इन बच्चों के कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में शुरू की गई 'बाल श्रमिक विद्या योजना' के तहत आठ से 18 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसमें कहा गया कि वर्तमान में यह योजना 20 जिलों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जिलों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 'सेवामित्र व्यवस्था' को रोजगार और जनसुविधा का अभिनव मॉडल बताया और इसे अधिक प्रभावी तथा जनोपयोगी बनाने पर जोर दिया।

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2021 से संचालित इस व्यवस्था के तहत नागरिक मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और कॉल सेंटर के माध्यम से घरेलू सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में पोर्टल पर 1,097 सेवा प्रदाता, 5,049 सेवामित्र और 54,747 कुशल कामगार पंजीकृत हैं।

मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में भी आवश्यकता के अनुसार सेवामित्र व्यवस्था के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

अमेरिका फर्स्ट वीसा शेड्यूलिंक क्या है? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारतीय को दिया 'रिटर्न गिफ्ट'

(जीएनएस)।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर हैं। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि, अमेरिका भारतीय बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए नया 'अमेरिका फर्स्ट वीजा शेड्यूलिंग टूल' ?शुरू करने जा रहा है।

उन्होंने इसे भारत-अमेरिका रिश्तों को और मजबूत करने वाला कदम बताया। रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की दोस्ती का भी जिक्र किया। माना जा रहा है कि इस नए सिस्टम से भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही रुबियो ने क्वाड और इंडो-पैसिफिक रणनीति में भारत की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। मार्को रुबियो के मुताबिक यह नया टूल खास तौर पर बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद वीजा इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट प्रक्रिया को ज्यादा तेज और आसान बनाना है। अमेरिका मानता है कि बिजनेस, टेक्नोलॉजी और निवेश से जुड़े लोग भारत-अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को प्राथमिकता देकर उनकी यात्रा और कामकाज को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है।

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

रुबियो ने साफ किया कि यह बदलाव हर वीजा आवेदक के लिए नहीं होगा। इसका फायदा मुख्य रूप से बिजनेस प्रोफेशनल्स, निवेशकों, टेक एक्सपर्ट्स और उन लोगों को मिल सकता है जो भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में अहम भूमिका निभाते हैं। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच बिजनेस ट्रैवल और कॉरपोरेट सहयोग बढ़ेगा। लंबे इंतजार और अपॉइंटमेंट की परेशानी से भी कुछ हद तक राहत मिल सकती है।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

सम्पादकीय

पीएम की पांच दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान रहे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि

पीएम मोदी की रोम की यह यात्रा दशार्ती है कि जब नेतृत्व सशत्त हो, द्दष्टि स्पष्ट हो और राष्ट्रीय हित सवरेपरि हों, तब परिणाम इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यह वह समय है जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है और भारत उसमें दर्शक नहीं, सव्रिय निमार्ता की भूमिका निभा रहा है।

मेलोनी को टॉफी, विपक्ष को तमाचा-मोदी ने रोम में नया इतिहास रचा रोम की ऐतिहासिक प्राचीरों के साए में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉंजिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी का पैकेट भेंट किया, तो दुनिया ने सिर्प एक मीठा पल नहीं, बल्कि वैश्विक विश्व व्यवस्था में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव का स्पष्ट संकेत देखा। यह 'मेलोडी'

डिप्लोमेसी महज वायरल सेल्फी या कोलोसियम की सैर नहीं थी। यह दो मजबूत राष्ट्रवादियों के बीच उस रणनीतिक गठबंधन की शुरूआत थी,जो यूरोप के मध्य में भारत को नया द्वार खोल रहा है। जबकि विपक्ष 'टॉफी डिप्लोमेसी' पर तंज कस रहा है, हकीकत यह है कि मोदी की इस यात्रा ने भारत-इटली संबंधों को 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' स्तर पर ऊंचा उठा दिया है। पुरानी कांग्रेस संस्वृति की 'चाय पी लो' वाली आलोचना अब पुरानी पड़ चुकी है। वैश्विक वूटनीति के बदलते परिद्दश्य के बीच इस दौरे में दोनों देशों ने संयुत्त 'जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029' की समीक्षा की और कई ठोस आउटकम्स/एम.ओ.यूज़ पर सहमति जताई। द्विपक्षीय व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। रक्षा उद्योग सहयोग, व्रिटिकल मिनरल्स, समुद्री परिवहन, वृषि, उच्च शिक्षा, नर्स भता और आयुव्रेद जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक समझौते हुए। सबसे महत्वपूर्ण, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को नई गति मिली। इटली भूमध्य सागर का अहम प्रवेश द्वार है, जिससे यह साझेदारी भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को 'एक्ट वेस्ट' की दिशा में भी मजबूत आधार देती है। जबकि विपक्ष 'मेलोडी' पर व्यंग्य कर रहा है, वास्तविकता यह है कि मोदीमेलोनी ने दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की ठोस नींव रखी है। यह यात्रा महज द्विपक्षीय नहीं,बल्कि बहुपक्षीय महत्व की है। दोनों नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। चीन के बढ़ते आामक रवैये,ऊर्जा सुरक्षा और आपरूति श्रृंखला की विविधता पर सहमति बनी। दोनों देशों ने एक्शन प्लान की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों के नेतृत्व वाले एक मैकेनिज़्म के गठन पर सहमति जताई है। यह संस्थागत मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेलोनी की सरकार मजबूत राष्ट्रवादी रुख के साथ अवैध प्रवासन और यूरोपीय संप्रभुता पर सख्त नीति अपनाती है,जबकि मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' और मेलोनी की 'इटली फर्स्ट' सोच में स्पष्ट समानता दिखती है। दोनों ने साफ संदेश दिया कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की नींव पर खड़े देश एक-दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, वैश्विक संतुलन को नई दिशा दे सकते हैं। यह वह सोच है जिससे कांग्रेस और उसके गठबंधन वाले हमेशा कतराते रहे। वे तो अभी भी'चीन भाई-चीन'वाली पुरानी लीक पर अटके हैं। इतिहास के पन्नों में यह यात्रा केवल राजनीतिक नहीं,बल्कि सांस्वृतिक जुड़ाव की एक सशत्त मिसाल के रूप में दर्ज हुई। कोलोसियम में संयुत्त भ्रमण, राजकीय रात्रिभोज, गार्ड ऑफ ऑनर और मेलोनी द्वारा हिंदी कहावत 'परिश्रम ही सफलता की वुंजी है' का उल्लेख-ये सभी क्षण दोनों देशों के बीच बढ़ती आत्मीयता को दशार्ते हैं। इटली में भारतीय समुदाय की उपस्थिति और सव्रियता लगातार मजबूत हो रही है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। भले ही वुछ लोग सांस्वृतिक वूटनीति को कम आँकते हों,पर वास्तविकता यह है कि सॉफ्ट पावर के बिना वैश्विक प्रभाव अधूरा रहता है,और इसी संतुलन को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। भारत और यूरोप के बीच आर्थिक रिश्ते अब नए विस्तार की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 16.77 बिलियन डॉलर के व्यापार आधार के साथ यह साझेदारी निवेश,तकनीक और संयुत्त उत्पादन को नई ऊर्जा दे रही है। रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन के अवसर मजबूत हो रहे हैं,वहीं स्वच्छ ऊर्जा और एआई जैसे भविष्य-वेंद्रित क्षेत्रों में सहयोग भारत को यूरोपीय तकनीकी क्षमता से और अधिक जोड़ रहा है। वैश्विक आपरूति श्रृंखला को चीन से अलग करने की चल रही कोशिशों के बीच भारत की रणनीतिक भूमिका लगातार बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदशा नीति ने इस परिवर्तन में भारत को निर्णायक स्थिति में ला खड़ा किया है,जबकि विपक्ष अब भी बड़े आर्थिक द्दष्टिकोण की बजाय सीमित मुद्दों तक ही सिमटा दिखाई देता है। विपक्ष की आलोचना इस दौर की एक चिताजनक सच्चाई बनकर सामने आती है। राहुल गांधी जैसे नेता जब 'टॉफी डिप्लोमेसी' पर व्यंग्य करते हैं,तो वे देश की गरिमा और विदेश नीति की गंभीरता को कमजोर करते प्रतीत होते हैं। जब भारत वैश्विक पटल पर मजबूती से अपनी स्थिति स्थापित कर रहा है,तब भी उन्हें विदेश नीति केवल 'मोदी का प्रचार' कहकर सीमित करने की प्रवृत्ति से आगे बढ़ते नहीं देखा जाता। यह भी स्मरणीय है कि वही विपक्ष पहले 'चीन के साथ दोस्ती' जैसे विचारों को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी इटली जैसे मजबूत यूरोपीय देश के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं,तब उनकी चुप्पी या तीखी आलोचना दोनों ही व्यापक राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में प्रश्न उठाती है। मोदी-मेलोनी की यह 'मेलोडी', डिप्लोमेसी अब केवल एक वूटनीतिक संवाद नहीं,बल्कि बदलती वैश्विक शत्ति संरचना में भारत के निर्णायक उभार का स्पष्ट संकेत बन चुकी है। रोम की यह यात्रा दशार्ती है कि जब नेतृत्व सशत्त हो, द्दष्टि स्पष्ट हो और राष्ट्रीय हित सवरेपरि हों,तब परिणाम इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यह वह समय है जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है और भारत उसमें दर्शक नहीं, सव्रिय निमार्ता की भूमिका निभा रहा है।

₹143579 करोड़ की 5th जेन फाइटर जेट डील, पाकिस्तान ने बढ़ाई भारत की टेंशन, राफेल से कितना ताकतवर यह एयरक्राफ्ट

दुनियाभर में सामरिक हालात लगातार बदल रहे हैं. बदलते माहौल के तहत तमाम देश अपने डिफेंस सिस्ट टम को लगातार एडवांस और अपग्रेड करने में जुटा है. भारत भी इसका अपवाद नहीं है. स्वदेशी स्तर पर नेक्स्ट जेनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करने को लेकर खास प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. इसके सथ ही सवा तीन लाख करोड़ रुपये में फ्रांस से 114 राफेल F4 जेट खरीदने का करार भी किया गया है. दूसरी तरफ, पाकिस्तान भी अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटा है. इसके तहत बड़ा कदम उठाया गया है.

पाकिस्तान ने तुर्की के साथ पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर अरबों डॉलर का सौदा किया है. हालांकि, दोनों देशों की ओर से इस करार की पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है.

भारत पूरी प्लानिंग के तहत अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है. फाइटर जेट से लेकर मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम तक डेवलप किए जा रहे हैं. फ्रांस से 114 राफेल जेट खरीदने का सौदा किया गया है. इसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताया जा रहा है. वहीं, नेक्स्ट जेनरेशन का फाइटर जेट बनाने के लिए स्वेदशी स्तर पर AMCA प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. इसका उद्देश्य पांचवीं पीढ़ी और उससे आगे का लड़ाकू विमान डेवलप करना है. चीन पहले ही 5th जेनरेशन का स्टील्थ जेट बना चुका है. अब पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि पाकस्तिान ने तुर्की के साथ बड़ी डिफेंस डील की है, जिसके तहत इस्ला लामाबाद पांचवीं पीढ़ी का 65 फाइटर जेट खरीदेगा. हालांकि, अभी तक दोनों देशों की तरफ से इस महाडील की पुष्टि नहीं की गई है. ऐसा होने पर दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस गड़बड़ा सकता है. यदि मीडिया रिपोर्ट सही है तो पाकस्तिान का यह कदम चीन के प्रति उसके मोहभंग को भी दिखाता है. इससे पहले इस बात की चर्चा थी कि पाकिस्तान अपने परंपरागत सहयोगी चीन से पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन अब इस्लामाबाद ने अंकारा का रुख कर लिया है

तुर्की और पाकिस्तान के बीच कथित तौर पर 65 अत्याधुनिक ङअअठ फिफ्थ जेनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर 15 अरब डॉलर (₹143579 करोड़ भारतीय मुद्रा में, पाकिस्तान मुद्रा में 417741 करोड़ रुपया) की बड़ी डिफेंस डील की खबर ने वैश्विक रक्षा जगत में हलचल पैदा कर दी है. 'इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग' की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के एक डफिंस जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच यह समझौता हो चुका है, हालांकि अभी तक न तो पाकिस्तान सरकार और न ही तुर्की की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है. यदि यह समझौता सही साबित होता है, तो यह पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक माना जाएगा. साथ ही यह तुर्की के स्वदेशी फिफ्थ जेनरेशन लड़ाकू विमान कार्यक्रम KAAN के लिए भी बड़ा निर्यात अवसर साबित हो सकता है. KAAN (जिसे पहले TF- या MMU नाम से जाना जाता था) तुर्की का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट है. इसे अत्याधुनिक एवियोनिक्स, कम रडार पहचान क्षमता और एयर सुपीरियोरिटी मिशनों के लिए विकसित किया गया है.

तुर्की का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट TAI KAAN तेजी से अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार में अपनी पहचान बना रहा है. इसे Turkish Aerospace Industries (TAI) ने विकसित किया है और इसने फरवरी 2024 में अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी. फ्रांस द्वारा विकसित डसॉल्ट राफेल F4 एक अत्याधुनिक 4.5वीं पीढ़ी का मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे एयर सुपीरियरिटी, न्यूक्लियर डिटरेंस और डीप-स्ट्राइक मिशनों के लिए तैयार किया गया है. यह राफेल के सबसे आधुनिक संस्करणों में गिना जाता है.

KAAN एक ट्विन-इंजन, ऑल-वेदर और एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर विमान है, जिसे कम रडार पहचान (Low Radar Cross Section) और स्टेल्थ क्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. विमान में इंटरनल वेपन बे दिए गए हैं, जिससे इसकी रडार विजिबिलिटी और कम हो जाती है. राफेल F4 की सबसे बड़ी खासियत इसकी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता है. यह फाइटर जेट सैटेलाइट, ग्राउंड कमांड नेटवर्क और अन्य लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है, जिससे युद्धक्षेत्र में तेज और सटीक फैसले लेने में मदद मिलती है.

विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपरक्रूज क्षमता मानी जा रही है. ट्विन-इंजन कॉन्फिगरेशन के कारण यह बिना आफ्टरबर्नर के लंबे समय तक सुपरसोनिक गति बनाए रखने में सक्षम होगा. इस विमान में अपग्रेडेड RBE2 AESA रडार, एडवांस SPECTRA इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और थेल्स स्कॉर्पियन हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले जैसे आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं. इससे पायलट को दुश्मन के लक्ष्यों की तेजी से पहचान और ट्रैकिंग में मदद मिलती है.

KAAN में तुर्की की स्वदेशी एवियोनिक्स और सेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें Aselsan द्वारा विकसित Karat Infrared Search and Track (IRST) सिस्टम और Toygun इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगाया गया है. इसके अलावा KEMENT Tactical Data Link के जरिए यह रियल टाइम नेटवर्किंग और ड्रोन के साथ संयुक्त ऑपरेशन करने में सक्षम होगा. हथियार क्षमता के मामले में राफेल F4 लंबी दूरी की

Meteor BVR मिसाइल और 1,000 किलोग्राम तक के अरट1000 प्रिसिजन गाइडेड बम ले जाने में सक्षम है. इसके अलावा इसमें अकसहायता प्राप्त टार्गेटिंग सिस्टम और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस तकनीक भी शामिल की गई है.

Turkish Aerospace Industries के अनुसार, KAAN की शुरूआती डिलीवरी 2028 के अंत तक तुर्की वायुसेना को शुरू करने का लक्ष्य है, जबकि इसकी पूर्ण ऑपरेशनल क्षमता 2030 के शुरूआती वर्षों तक हासिल होने की उम्मीद है. इस बीच इंडोनेशिया समेत कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई है और पाकिस्तान व सऊदी अरब के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ने की चर्चा है. फ्रांस की वायुसेना और नौसेना में राफेल F4.1 मुख्य ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है. वहीं भारत ने 114 राफेल विमानों की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है. भारतीय संस्करण को F4+ कहा जा रहा है, जिसमें स्वदेशी हथियार, सुरक्षित डेटा लिंक और स्टील्थ विमान पहचानने में सक्षम उन्नत रडार शामिल होंगे. इन विमानों का बड़ा हिस्सा नागपुर में असेंबल किए जाने की योजना है.

लंबे समय से पक रही थी खिचड़ी

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से KAAN कार्यक्रम में रुचि दिखाता रहा है. दोनों देशों के बीच पहले भी खत्र्-17 लड़ाकू विमान जैसे कई रक्षा सहयोग कार्यक्रम चल चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी इंजीनियर भी ङअअठ प्रोजेक्ट के विकास में शामिल रहे हैं और ज्वाइंट प्रोडक्शन फैशिलिटी स्थापित करने पर भी चर्चा हो चुकी है. ऐसे में यह डील केवल विमान खरीद तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन जैसे बड़े औद्योगिक सहयोग का रास्ता भी खोल सकती है. पाकिस्तान के लिए यह सौदा उसकी वायु शक्ति में बड़ा रणनीतिक बदलाव ला सकता है. यदि उसे बड़ी संख्या में फिफ्थ जेनरेशन स्टील्थ विमान मिलते हैं, तो उसकी वायुसेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. माना जा रहा है कि ये विमान पाकिस्तान के मौजूदा लड़ाकू बेड़े के साथ मिलकर क्षेत्रीय संतुलन और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो हजारों करोड़ की इस डील के तहत पाकिस्तान मित्र देश तुर्की से 65 स्टील्थ एयरक्राफ्ट खरीदेगा.

दूसरी ओर, तुर्की के लिए यह डील उसके रक्षा निर्यात कार्यक्रम की बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है. राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की पिछले कुछ वर्षों से अपनी घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, ताकि विदेशी हथियार पर निर्भरता कम की जा सके. ङअअठ प्रोजेक्ट ट इसी रणनीति का प्रमुख हिस्सा मानी जाती है. तुर्की पहले ही अपने वायुसेना कार्यक्रम के लिए ङअअठ के शुरूआती करार कर चुका है और अब मित्र देशों को इसका निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इंडोनेशिया और अजरबैजान जैसे देशों के साथ भी ङअअठ को लेकर बातचीत चल रही है. ऐसे में पाकिस्तान के साथ संभावित समझौता तुर्की को फिफ्थ जेनरेशन लड़ाकू विमान बाजार में एक नए खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है.

तुर्की-पाकिस्तान के बीच किस डिफेंस डील का दावा किया गया है?

एक तुर्की रक्षा पत्रकार ने दावा किया है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच 65 ङअअठ फिफ्थ-जेनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स की खरीद के लिए करीब 15 अरब डॉलर की बड़ी रक्षा डील हुई है. अगर यह समझौता सही साबित होता है, तो यह पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में शामिल होगा.

KAAN फाइटर जेट की खासियत क्या है?

ङअअठ तुर्की का स्वदेशी फिफ्थ-जेनरेशन स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे पहले TF- या MMU नाम से भी जाना जाता था. इसमें लो-ऑब्जर्वेबल स्टील्थ डिजाइन, आधुनिक एवियोनिक्स, एयर सुपीरियॉरिटी क्षमता और एडवांस हथियार प्रणाली जैसी खूबियां शामिल हैं.

क्या इस डील की आधिकारिक पुष्टि हुई है?

फिलहाल पाकिस्तान सरकार, क्रढफ तुर्की के रक्षा मंत्रालय या से इस डील की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इसलिए इस खबर को लेकर अभी सतर्कता बरती जा रही है.

पाकिस्तान को इस डील से क्या रणनीतिक फायदा हो सकता है?

अगर पाकिस्तान को ङअअठ जेट्स मिलते हैं, तो उसकी वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा. इससे पाकिस्तान की स्टील्थ और एयर कॉम्बैट क्षमता मजबूत होगी, साथ ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता है.

तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा सहयोग का महत्व क्या है?

दोनों देशों के बीच पहले से खत्र्-17 जैसे प्रोजेक्ट्स में सहयोग रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के इंजीनियर ङअअठ प्रोग्राम में भी योगदान दे रहे हैं. संभावित डील से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, संयुक्त उत्पादन और दीर्घकालिक रक्षा औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा मिल सकता है.

अभी तक डिफेंस डील की पुष्टि नहीं

हालांकि, फिलहाल इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि का अभाव बना

लगातार सस्ती हो रही चांदी, आज भी गिरे दाम? कितना है एक किलो सिल्वर का रेट

(जीएनएस)। महंगाई और बाजार में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच अब लोग निवेश के लिए सिर्फ सोने पर ही निर्भर नहीं रह रहे हैं। चांदी भी धीरे-धीरे लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, क्योंकि कम बजट में इसमें निवेश करना आसान माना जाता है। यही वजह है कि छोटे निवेशक से लेकर आम परिवार तक चांदी की खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

शादी-ब्याह, त्योहार और गिफ्टिंग में भी चांदी की मांग हमेशा बनी रहती है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में चांदी के दाम में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए लोग इसके ताजा रेट पर नजर बनाए हुए हैं। आज चांदी की कीमत ₹285 प्रति ग्राम और ₹2,85,000 प्रति किलो दर्ज की गई है।

आज चांदी के ताजा भाव

आज भारत में चांदी की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ज्यादातर शहरों में रेट स्थिर बने हुए हैं।

1 ग्राम चांदी – ₹285

8 ग्राम चांदी – ₹2,280

10 ग्राम चांदी – ₹2,850

100 ग्राम चांदी – ₹28,500

1 किलो चांदी – ₹2,85,000

पिछले 10 दिनों में कैसे बदले

दाम

पिछले कुछ दिनों में चांदी के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। कभी तेजी तो कभी गिरावट के कारण निवेशकों की नजर लगातार बाजार पर बनी हुई है।

22 मई 2026 – ₹2,85,000 प्रति किलो

21 मई 2026 – ₹2,85,000 प्रति किलो

20 मई 2026 – ₹2,80,000 प्रति किलो

19 मई 2026 – ₹2,85,000 प्रति किलो

18 मई 2026 – ₹2,90,000 प्रति किलो

17 मई 2026 – ₹2,80,000 प्रति किलो

16 मई 2026 – ₹2,80,000 प्रति किलो

15 मई 2026 – ₹2,90,000 प्रति किलो

14 मई 2026 – ₹3,00,000 प्रति किलो

13 मई 2026 – ₹3,10,000 प्रति किलो

बड़े शहरों में चांदी का भाव

देश के कई बड़े शहरों में आज चांदी के रेट लगभग समान बने हुए हैं।

दिल्ली – ₹2,85,000 प्रति किलो

मुंबई – ₹2,85,000 प्रति किलो

जयपुर – ₹2,85,000 प्रति किलो

लखनऊ – ₹2,85,000 प्रति किलो

पुणे – ₹2,85,000 प्रति किलो

अहमदाबाद – ₹2,85,000 प्रति किलो

पटना – ₹2,85,100 प्रति किलो

MCX पर चांदी का भाव

मल्टी कमोडिटी बाजार में शुक्रवार सुबह चांदी के वायदा भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली। 03 जुलाई 2026 एक्सपायरी वाली चांदी ₹274662 प्रति किलो पर कारोबार करती नजर आई, जिसमें ₹221 यानी करीब 0.08 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। आज के कारोबार के दौरान चांदी का न्यूनतम भाव ₹273266 और उच्चतम भाव ₹275000 तक पहुंचा।

वहीं इसका पिछला बंद भाव ₹274883 रहा। बाजार आंकड़ों के अनुसार, चांदी का औसत भाव ₹274331.83 प्रति यूनिट दर्ज किया गया। इस दौरान कुल 464 लॉट का कारोबार हुआ, जबकि ओपन इंटरेस्ट 9219 लॉट रहा। एक्सपट्र्स का मानना है कि वैश्विक बाजार और निवेशकों की खरीदारी के असर से आने वाले दिनों में चांदी के दाम में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

आ गया एलपीजी का स्वदेशी विकल्प! देश का पहला डाइमिथाइल ईथर प्लांट में उत्पादन शुरू, रसोई गैस की टेंशन होगी खत्म

(जीएनएस)। भारत ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बालाजी एमाइंस लिमिटेड द्वारा देश का पहला वाणिज्यिक स्तर का डाइमिथाइल ईथर (ऊटए) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट (विनिर्माण संयंत्र) चालू करके, दूसरे ईंधन को अपनाने और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है.

कंपनी ने 20 मई से चिंचोली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में अपनी 100,000 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) DME प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. यह प्रोजेक्ट वैश्विक भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं और अस्थिर ऊर्जा बाजार के बीच आयातित एलपीजी पर निर्भरता कम करने की भारत की कोशिशों में एक संभावित गेम चेंजर के तौर पर सामने आया है.

क्ल्ल्रि ⁄१२३ ीै ्रं'३८ ुॅल्लर स्र१ङ्गष्ठि३ङ्गल्ल रीीर २ूङ्गस्री ३ङ्ग ू४३ छढक्ष्स्रङ्ग१३२ ल्ल ि ेंल्ली१ ।थ्री' ३ॅ३

डाइमिथाइल ईथर (DME) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सोलापुर (ETV ईं१३)

डाइमिथाइल ईथर को एक क्लीन-बर्निंग फ्यूल माना जाता है जो या तो LPG को पूरी तरह से हटा सकता है या उसके साथ ब्लेंड किया जा सकता है. यूरोप और एशिया के कई देश पहले से ही LPG के साथ 20 प्रतिशत तक के अनुपात में ऊटए को ब्लेंड करते हैं. भारत में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने हाल ही में एलपीजी के साथ 8 प्रतिशत तक डाइमिथाइल ईथर को ब्लेंड करने की इजाजत दी है, जिससे घरेलू ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र में इसे धीरे-धीरे अपनाने का रास्ता खुल गया है.

यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी LPG जरूरतों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा आयात करता है, जिससे देश को ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों और मिडिल ईस्ट और दूसरे ऊर्जा बनाने वाले इलाकों में तनाव से जुड़ी कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, अनुभवी वैज्ञानिक और नीति आयोग के पूर्व सदस्य वी के सारस्वत ने कहा, "डाइमिथाइल ईथर (DME) एक जरूरी वैकल्पिक ईंधन के तौर पर उभर रहा है. यह या तो एलपीजी का स्थान ले सकता है या फिर इसके साथ मिलाकर इम्पोर्टेड छढक्र पर भारत की भारी निर्भरता को कम कर सकता है."

उन्होंने बताया कि, इसका मकसद लंबे समय के लिए देसी तकनीक और स्थानीय फीडस्टॉक संसाधन का इस्तेमाल करके ऊटए को देश में ही बनाना है. उनके मुताबिक, डाइमिथाइल ईथर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्चा माल मेथनॉल, कोयला आधारित प्रक्रिया सहित कई तरीकों से बनाया जा सकता है.

सारस्वत ने बताया कि देसी डाइमिथाइल ईथर टेक्नोलॉजी को नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (NCL), पुणे ने कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पहले ही डेवलप कर लिया है. उन्होंने कहा, "जबकि एक पायलट प्लांट पहले से ही चालू है, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी इम्पोर्टेड मेथनॉल का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है."

अगर बालाजी एमाइंस प्लांट को पूरी कैपेसिटी से चलाया जाए, तो यह हर साल करीब 100,000 टन मेथनॉल की खपत करेगा. इंडस्ट्री के आकलन से पता चलता है कि मार्केट में चल रही अनिश्चितताओं की वजह से दुनिया भर में मेथनॉल की कीमतें

लगातार बदल रही हैं. बालाजी एमाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर राम रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट को भारत के एनर्जी सिक्योरिटी लक्ष्यों के लिए एक रणनीतिक मील का पत्थर बताया.

रेड्डी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. अभी, भारत विदेशों से बड़ी मात्रा में छढक्र आयात करता है, और दुनिया भर में चल रही भू-राजनीतिक मुश्किलों की वजह से, हमने देखा है कि वैश्विक हालात भारत की एनर्जी सप्लाई चेन पर सीधे असर डाल सकते हैं. यह देश के लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का सही समय है."

कंपनी का मानना है कि डाइमिथाइल ईथर में होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, बिस्किट बनाने, एयरोसोल एप्लीकेशन, सिरेमिक, बल्ब बनाने और दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर में बड़ा कमर्शियल पोटेंशियल है, जो बल्क LPG खपत पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं. रेड्डी ने कहा, "क्योंकि डाइमिथाइल ईथर को एलपीजी के साथ ब्लेंड किया जा सकता है और मौजूदा आधारभूत संरचना के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए यह आने वाले सालों में भारत के लिए एक सस्ता और व्यावहारिक वैकल्पिक ईंधन बन सकता है."

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि एलपीजी और DME के बीच सीधे मूल्य तुलना अभी मुश्किल है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी संकट और ग्लोबल मार्केट में बड़े पैमाने पर अस्थिरता के कारण कच्चा माल के दाम में तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा है.

डाइमिथाइल ईथर को लेकर जोश के बावजूद, इंडस्ट्री एक्सपट्र्स का कहना है कि भारत की घरेलू मेथनॉल उत्पादन क्षमता सीमित है. सारस्वत ने कहा कि कई भारतीय मेथनॉल उत्पादक अभी नेचुरल गैस सप्लाई पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, जिससे आयात निर्भरता की एक और लेयर बन जाती है.

सारस्वत ने कहा, "भविष्य में इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए, भारत को मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए कोयला गैसीकरण पर ध्यान देना चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने पहले ही 37,500 करोड़ रुपये का कोल गैसीफिकेशन मिशन शुरू कर दिया है, जिसका मकसद इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना है. एक्सपट्र्स के अनुसार, डाइमिथाइल ईथर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह भारत के मौजूदा छढक्र डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ अनुकूल है. सारस्वत ने बताया कि स्टोरेज सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेंडर और बर्नर काफी हद तक डाइमिथाइल ईथर के साथ अनुकूल हैं, जिनमें सिर्फ मामूली बदलाव की जरूरत है. उन्होंने कहा, "DME के LPG से सस्ता होने की उम्मीद है, जिससे घरों, होटलों, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योग को फायदा होगा." भारत अभी 8 प्रतिशत ब्लेंडिंग मॉडल के साथ सावधानी से शुरूआत कर रहा है. सारस्वत ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियां अभी भी प्लानिंग फेज में हैं और किसी भी देशव्यापी लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'भारत ने 8 फीसदी ब्लेंडिंग मॉडल के साथ शुरूआत की है और टेस्टिंग और वैलिडेशन स्टडीज पूरी होने के बाद भविष्य में इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 20 फीसदी करने का लक्ष्य है.' रेड्डी ने भी इसी तरह के फेज्ड तरीके को दोहराया, और कहा कि 8 फीसदी से 12 फीसदी ब्लेंडिंग से शुरू करने से इंडस्ट्री को मौजूदा LPG इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए बिना डाइमिथाइल ईथर अपनाने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा, "इसके बाद, ब्लेंडिंग अनुपात को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, ऑपरेशनल अडैप्टेशन और पूरे सेक्टर में इसे आसानी से लागू करने के लिए काफी समय मिलेगा.' कंपनी ने यह भी बताया कि वह डाइमिथाइल ईथर ब्लेंडिंग और अपनाने की रणनीति के बारे में मंत्रालयों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है.

हालांकि, इस नए सेक्टर के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल एक बड़ी रुकावट बनी हुई है. रेड्डी के मुताबिक, बालाजी एमाइंस को रोड टैंकर, स्टोरेज सिस्टम और सिलेंडर के लिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से परमिशन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि कमर्शियल लेवल पर ऊटए प्रोडक्शन भारत में नया है.

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307

मुख्यमंत्री योगी की घोषणा, देवरिया में सोनूघाट-बरहज फोरलेन सड़क का निर्माण जल्द

(जीएनएस)।

देवरिया। जिले में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोनूघाट-बरहज मार्ग का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। यह सुनकर उमड़ी जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम के आश्वासन के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि अब जल्द ही इस मार्ग का निर्माण शुरू होगा।

दरअसल, सोनूघाट-बरहज फोरलेन निर्माण की स्वीकृति शासन से कई माह पहले ही मिल चुकी थी। शासन ने इसके निर्माण के लिए 172 करोड़ 25 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। साथ ही पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए थे। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

सूत्रों के अनुसार, सड़क निर्माण के लिए मिली 10 करोड़ की पहली किस्त को बिजली विभाग को देकर विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराई गई, जिससे सड़क का काम लटक गया।

बरहज से सोनूघाट के बीच की दूरी 21.750 किलोमीटर है। वर्तमान में इसकी चौड़ाई सात मीटर है। अब इसे फोरलेन बनाया जाएगा।

प्रत्येक लेन की चौड़ाई सात मीटर होगी और दोनों लेन के बीच दो मीटर का डिवाइडर बनाया जाएगा। क्षेत्रवासी लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब क्षेत्र की जनता ने राहत की सांस ली है। लोगों को भरोसा है कि जल्द ही इस मार्ग का निर्माण शुरू होगा और आवागमन सुगम हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पिछली बार 29 अप्रैल को देसही ब्लाक के पड़ियापार में आयोजित लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में 501 परियोजनाओं पर करीब सात अरब रुपये की सौगात दी थी। इसके एक साथ बाद ही शुक्रवार को पथरदेवा, रामपुर कारखाना व सदर ब्लाक में 19 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जिस पर 655.45 करोड़ रुपये लागत आई है।

मुख्यमंत्री ने सात विधानसभा में केवल तीन विधानसभा से जुड़े कार्य होने पर उन्होंने लोगों को जरूरत के हिसाब से आवश्यक कार्यों को पूरा करने का विश्वास दिलाया। जिसमें सोनूघाट-बरहज की सड़क का भी जल्द निर्माण कार्य कराए जाने की बात दोहराई।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने देवरिया से काफी अधिक लगाव होने की बात कही। मुख्यमंत्री के भाषण के पूर्व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योगी जी इसके पहले 29 अप्रैल को देवरिया आए तो सात अरब का सौगात दे गए। उन्होंने कहा कि ऐसे महान व्यक्ति का इस धरती पर बारंबार स्वागत है। वे ऐसे ही सौगात लेकर बार-बार आए ताकि क्षेत्र व जनपद का विकास हो सके।

किस मंत्रालय का कैसा रहा काम, किसका परफॉर्मेंस बेस्ट? मोदी सरकार ने पहली बार बनाई मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट

(जीएनएस)।

करीब साढ़े चार घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि शासन में सुस्ती और फाइलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों की जिंदगी को आसान बनाना होना चाहिए और हर योजना का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार मंत्रालयों और विभागों के कामकाज का विस्तृत मूल्यांकन किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार मंत्रालयों और विभागों के कामकाज का विस्तृत मूल्यांकन किया है. इस विशेष समीक्षा में फाइलों के निपटारे की रफ्तार, जनता की शिकायतों के समाधान, कैबिनेट नोट्स पर समय पर जवाब और प्रशासनिक कार्यकुशलता जैसे कई अहम पैमानों पर मंत्रालयों का प्रदर्शन परखा गया.

बताया जा रहा है कि यह अभ्यास सरकार के भीतर जवाबदेही बढ़ाने और फैसलों की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से किया गया. कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रालयों के प्रदर्शन की रिपोर्ट पेश की.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब साढ़े चार घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि शासन में सुस्ती और फाइलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों की जिंदगी को आसान बनाना होना चाहिए और हर योजना का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचना चाहिए.

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया, अलग-अलग मानकों पर मंत्रालयों का आकलन किया गया, हालांकि सभी पैरामीटर को जोड़कर कोई एक ओवरऑल रैंकिंग जारी नहीं की गई. रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता मामले मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय कई श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों में शामिल रहे.

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने जन शिकायत निवारण और पश्चिम एशिया संकट से जुड़े प्रबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. वहीं कोयला मंत्रालय को फाइल निपटान और प्रशासनिक प्रबंधन के मामले में सबसे अधिक अंक मिले. बिजली और स्वास्थ्य मंत्रालयों को भी प्रभावी कामकाज के लिए सराहा गया.

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 'विकसित भारत 2047' के विजन को दोहराते हुए कहा कि यह केवल नारा नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि मंत्रालयों को कम समय में अधिक परिणाम देने होंगे और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा.

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सचिव की प्रस्तुति के बाद कई मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी शुरू कर दी हैं. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक में अधिकारियों से कहा कि किसानों और गरीबों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहिए. उन्होंने जन शिकायतों के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया.

सरकार का मानना है कि इस तरह की नियमित समीक्षा से मंत्रालयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ जल्दी मिल सकेगा.

ओलंपियाडः सीएम योगी ने किया विजेताओं का सम्मान; उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी किया सम्मानित, ये अतिथि रहे मौजूद

(जीएनएस)।

नई दिल्ली , अमर उजाला की ओर से गत वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर के लाखों छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से 12 तक के विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नेशनल रैंक-1 के विजेताओं को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है।

अमर उजाला की ओर से गत वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर के लाखों छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से 12 तक के विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नेशनल रैंक-1 के विजेताओं को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है।

18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसी कड़ी में 19 मई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल तथा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में नेशनल रैंक-1 के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इससे पहले 17 मई 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित समारोह में उत्तराखंड राज्य से चयनित नेशनल रैंक-1 के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इन मेधावियों को 21,000 रुपये नकद, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय टॉपर्स को भी भविष्य में आयोजित कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी अमर उजाला टीम द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर साझा की जाएगी। अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड-2026झ27 के विद्यार्थियों के लिए पुनः पंजीकरण शुरू हो चुका है। इस वर्ष ओलंपियाड में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए इंगलिश, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिरंग, हिंदी और टेक एंड एआई विषयों के लिए पंजीकरण खुले हैं।

पुरस्कृत : छात्र-छात्राऐं

सोहम कार्तिकेयन गोयल	दिल्ली पब्लिक स्कूल, रानीपुर	तनुज पटेल	सेक्रेड हार्ट किजुकेशन-2
समर टोपनो	डीपीएस रानीपुर	अरीन खान	लीड कन्वेंट स्कूल
अनुरुद्ध नेगी	डीएवी पब्लिक स्कूल	अभिलाषा सिंह	पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय, जनकपुरी
विशेष दसलिया	ऑरम द ग्लोबल स्कूल	आयुष कुमार गौर	बीआरएस कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
कुशी	दून कैम्ब्रिज स्कूल	मणिककर्णिका राठौर	वेदान विनायक इंटरनेशनल स्कूल
वंश बिष्ट	सेंट थेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल	वंश मोदी	श्री गुलाब राय मोंटेसरी सीनियर स्कूल
कुशाग्र जोशी	ऑरम द ग्लोबल स्कूल	अनन्या श्रीवास्तव	गीता देवी सरस्वती बाल शिक्षण संस्थान
निर्मय प्रताप सिंह	चिल्ड्रन्स अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल	जतिन अग्रवाल	सीएफ एंड्रूज स्कूल
वेद रंजन यादव	सेंट जॉन्स स्कूल	रासांश रवि	आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल
शौर्य मिश्रा	पीटीएल क्राइस्ट अकादमी, खटूरा	मानवी अग्रवाल	बालूनी पब्लिक स्कूल
सान्वी गुप्ता	सेंट जोसेफ एसआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल	अंशिका सिंह	इन्वेंटर पब्लिक स्कूल
हर्षवर्धन जयन	रेनबो स्कूल	दक्ष विनोद अग्रवाल	विश्वा भारती पब्लिक स्कूल
आयुष निषाद	एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल	अस्मी श्रीवास्तव	जीएम अकादमी
आदित्य श्योरन	लॉर्ड कृष्णा इंटर कॉलेज	ख्याति सिंह	सेंट क्लेर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल
अरुष बंसल	डीपीएस, गाजियाबाद मेरठ रोड	मानशी यादव	न्यू टाउन हॉल पब्लिक स्कूल / कॉलेज
ऑद्विक मिश्रा	जेबी अकादमी, अयोध्या	पूजा	एन एस डी एस विद्या मंदिर
समर चौबे	एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल	गुरमीत सिंह	एएसएम मॉडर्न अकादमी
अमोघ गुप्ता	सेंट थेरेसा स्कूल	सान्या	एक्मे ग्लोबल स्कूल
राघव सिंह गौतम	सेंट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल	जितेंद्र कुमार	डीकेएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल
रिदान शेफर्ड	आदर्श विद्यालय कंपोजिट, उरुला	अर्पिता शुक्ला	कर्मयोगी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज

सीएम योगी बोलेः राजस्व मुकदमों में देरी पर तय होगी अफसरों की जवाबदेही, दाखिल-खारिज में यह जिले सबसे कमजोर

(जीएनएस)।

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व मामलों का सही निपटारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। भूमि और राजस्व से जुड़े विवाद सामाजिक सौहार्द से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इन मामलों में देरी स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों की कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि आम नागरिक को शीघ्र न्याय मिल सके। निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित मुकदमों का अभियान चलाकर निस्तारण किया जाए।

सीएम ने कहा कि तहसील और जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा हो और कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।

भू उपयोग परिवर्तन में अमेठी समेत कई जिले पीछे

बैठक में बताया गया कि

आरसीसीएमएस पोर्टल के माध्यम से धारा-80 (भू-उपयोग परिवर्तन) के अंतर्गत लंबित वादों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। 1 जनवरी को कुल 85158 वाद लंबित थे, जिनमें से 77578 का निस्तारण किया गया था। वहीं 22 मई तक कुल लंबित वादों की संख्या घटकर 38166 रह गई, जिनमें 29543 वादों का निस्तारण किया गया। धारा-80 के मामलों में बस्ती, चित्रकूट, अयोध्या, बागपत और कन्नौज ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि मेरठ, वाराणसी, अमेठी, गौतमबुद्धनगर और हापुड़ का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया।

दाखिल खारिज में रामपुर-मुरादाबाद का प्रदर्शन कमजोर

बैठक में बताया गया कि धारा-34 (दाखिल खारिज) के अंतर्गत लंबित वादों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 1 जनवरी 2026 को कुल 2244466 वाद लंबित थे, जो 22 मई तक घटकर 1059139 रह गए। इस अवधि में 540945 वादों का निस्तारण किया गया। समीक्षा में बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और बदायूं का प्रदर्शन बेहतर पाया गया, जबकि गोरखपुर, संतकबीरनगर, प्रतापगढ़, बलिया और देवरिया अपेक्षित प्रगति नहीं कर सके।

पैमाइश में लखनऊ-अमेठी, कुर्रा बंटवारे में प्रतापगढ़-गोंडा पीछे

धारा-33 के अंतर्गत निर्विवादित वरासत के मामलों में 2025 में कुल 1689732 आवेदन मिले थे, जिनमें से 1643104 का निस्तारण किया गया। वहीं 22 मई तक प्राप्त 715872 आवेदनों में से 652512 का निस्तारण किया जा चुका है। धारा-24 (पैमाइश) के मामलों में गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, अमेठी और मुजफ्फरनगर अपेक्षित प्रगति नहीं कर सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। धारा-116 (कुर्रा बंटवारा) में वाराणसी, एटा, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज का प्रदर्शन बेहतर रहा, जबकि प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर, गोंडा और बलिया का प्रदर्शन कमजोर पाया गया।

यीडा में 17 निवेशकों को भूमि आवंटन, सीएम योगी बोले- यूपी बना देश की इकॉनमी का ब्रेकथ्रू

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के अंतर्गत 17 निवेशकों को शुक्रवार को भूमि आवंटन पत्र प्रदान किए. निवेशकों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी ने अब टूरिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के विश्वस्तरीय डेस्टिनेशन के रूप में खुद को स्थापित किया है. अपने उत्तर प्रदेश के ब्रांड एंबेसडर के रूप में प्रदेश की नई छवि को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है. यूपी में निवेश करने वाले निवेशक प्रदेश के विकास में सरकार के सहयात्री हैं.

सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने जिस जेवर क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है और जिस क्षेत्र में आपको अलाटमेंट लेटर वितरित किए गए हैं, आज से 9 वर्ष पहले यह भारत का सबसे डरावना क्षेत्र हुआ करता था. वहां गंभीर आपराधिक घटनाएं होती थीं. शाम पांच-साढ़े पांच बजे के बाद आवागमन बंद हो जाता था.लाइफ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही हुआ करती थी. इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन आज जेवर, यीडा क्षेत्र में जो परिवर्तन दिख रहा है, वह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, और यही हाल यूपी के हर जनपद का है.

यूपी में आर्म्स लाइसेंस रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले- 'अदृश्य शस्त्र' ज्यादा खतरनाक

2017 के पहले माफिया को वितरित किए गए थे जनपद

सीएम ने कहा कि 2017 के पहले सत्ता के सामानांतर माफिया का साम्राज्य हुआ करता था. हर जनपद में भय व दहशत का माहौल था. महिलाएं बाजार या रोजगार के लिए बाहर जाती थीं तो परिवार की चिंता होती थी कि वे सूर्यास्त के पहले वापस आ जाएं. व्यापारी 6 बजे के पहले प्रतिष्ठान बंद करने पर मजबूर थे. सड़कें गड्ढों से भरी थीं. कनेक्टिविटी, बिजली की हालत बुरी थी. मुश्किल से 4-5 घंटे बिजली मिल जाए तो लोग खुद को भाग्यशाली मानते थे. हर माफिया को अलग-अलग जनपद वितरित किए गए थे. माफिया व आपराधिक गिरोह के लोग जनपद व थाने का संचालन करते थे. सरकार के पास नीति, नीयत, सुरक्षा व लैंडबैंक भी नहीं था.

चारधाम यात्रा को लेकर स्वामी अरुण गिरी की श्रद्धालुओं को नसीहत, यात्रा पिकनिक नहीं

विकास की पहली शर्त है सुरक्षा

सुरक्षा को विकास की पहली शर्त बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाना पड़ता है. असुरक्षित वातावरण में कुछ भी नहीं हो सकता.आज यूपी में बिना रोकटोक, बिना लेनदेन, उद्योग-व्यापार अनुकूल नीतियों के लाभ दिखाई दे रहे हैं। अब यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है। देश में यदि प्रतिस्पर्धा हो तो यूपी टॉप राज्यों में होगा। एक्सप्रेसवे का 60 प्रतिशत हिस्सा और चार लाख किमी. का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास है. हर जिला मुख्यालय फोर-लेन, तहसील या ब्लाक मुख्यालय फोर-लेन/टू-लेन से जुड़ा है. यूपी की एयरकनेक्टिविटी सबसे अच्छी है. 2017 से पहले यूपी में डेढ़ एक्सप्रेसवे, दो एयरपोर्ट संचालित थे. आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं, उसमें से पांच अंतरराष्ट्रीय हैं. छह एयरपोर्ट पर हम काम कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट मिल जाएं तो इन्हें भी बहुत जल्द संचालित करेंगे.

निवेश के स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध

निवेशकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी के पास 16 हजार किमी. का रेल कॉरिडोर है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईस्टर्न/वेस्टर्न) का जंक्शन भी यूपी में है. जिस क्षेत्र में आपका निवेश हो रहा है, वहां रोड, फ्रेट कॉरिडोर, विश्व स्तरीय एयर कनेक्टिविटी भी है. वह क्षेत्र लाजिस्टिक हब बनने जा रहा है. यूपी के पास पहली रैपिड रेल, पहला इनलैंड वाटरवे (वाराणसी से हल्दिया) संचालित है। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने यूपी में लंबी छलांग लगाई है. सात शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है.

यूपी अब माफिया, गुंडा, कर्फ्यू, अराजकता, दंगा मुक्त

सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब माफिया, गुंडा, कर्फ्यू, अराजकता, दंगा से मुक्त है. यहां हर व्यक्ति, निवेशक को सुरक्षा की गारंटी है. हम निवेशक को केवल निवेशक नहीं मानते, बल्कि वह इन्वेस्टर पार्टनर के रूप में यूपी सरकार के साथ विकास में सहभागी बनकर कार्य करता है. यूपी में निवेश करने वाला निवेशक प्रदेश के विकास में सरकार का सहयात्री है. वह यूपी के नौजवानों को रोजगार देता है, उन्हें स्किलफुल बनाता है. सरकार हर निवेशक का यूपी में स्वागत करती है.

सीएम योगी ने कहा कि यूपी के पास 34 सेक्टोरल पॉलिसी हैं. एफडीआई की डेडिकेटेड पॉलिसी, फॉर्चून 500 की पॉलिसी है। 25 हजार हेक्टेयर का बड़ा लैंडबैंक यीडा के पास विकसित करने जा रहे हैं. बीडा नए इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित हो रहा है. इसमें कानपुर व झांसी के बीच 56 हजार एकड़ लैंड उपलब्ध होगी.

सीएम ने बताया कि गत वर्ष 156 करोड़ पर्यटक यूपी में आए. यूपी कभी बीमारू नहीं था. राजनीतिक नेतृत्व की मानसिकता ने इसे बीमार बनाया था. यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला राज्य था. गुंडों के पीछे दुम दबाकर चलने की प्रवृत्ति और माफिया के सामने नतमस्तक होने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने यूपी को बीमारू बनाया था, जब स्वस्थ मानसिकता के साथ डबल इंजन सरकार आई तो यूपी आज देश का इकॉनमी का ब्रेकथ्रू बन चुका है.

ट्विशा शर्मा के बाद सपना चौधरी को लेकर आई बड़ी खबर, शादी के 5 साल बाद ये क्या हुआ?

(जीएनएस)।

भोपाल में रह रहीं मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने जहां एक तरफ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं अब हरियाणवी इंडस्ट्री की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी और उनकी शादीशुदा लाइफ को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सपना चौधरी एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं।

क्या हुआ सपना चौधरी की शादीशुदा जिंदगी में?

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू (शी१ रैं४) के रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब खुद सपना चौधरी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

रिश्ता निभा रही हूं पर प्यार महसूस नहीं होता

-हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सपना चौधरी ने अपनी निजी जिंदगी के कई पहलुओं पर खुलकर बात की है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह एक पत्नी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभा रही हैं लेकिन रिश्ते में अब पहले जैसा एहसास नहीं बचा है।

-सपना चौधरी ने कहा कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं होता बल्कि वह एक ऐसा एहसास है जो इंसान की आत्मा को छू जाए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फैंस ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर सपना अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर इतना भावुक क्यों नजर आ रही हैं।

क्या पति वीर साहू से हुई सपना चौधरी की लड़ाई?

-इंटरव्यू के दौरान सपना चौधरी से ये भी पूछा गया कि पति-पत्नी के बीच जब मनमुटाव होता है तो पहले कौन मनाता है। इस सवाल पर सपना चौधरी ने बेहद बेबाक अंदाज में जवाब दिया।

-सपना चौधरी ने कहा कि उनके और वीर साहू के बीच लड़ाई जैसी स्थिति कम ही बनती है क्योंकि दोनों अपनी-अपनी राय खुलकर रखते हैं। सपना ने बताया कि वह अपनी बात कहकर आगे बढ़ जाती हैं और बेवजह बहस में समय बर्बाद करना पसंद नहीं करतीं।

'मेरे रिश्ते में बहुत कुछ 'धुंधला-धुंधला' दिख रहा है'

सपना चौधरी ने ये भी कहा कि हर रिश्ते में अलग-अलग सोच होना स्वाभाविक है लेकिन अब उन्हें रिश्तों में बहुत कुछ 'धुंधला-धुंधला' महसूस होने लगा है। उनकी ये बात फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे उनके रिश्ते की मौजूदा स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं।

सीएम योगी को कहा 'मूर्खमंत्री': हाईकोर्ट ने भीम आर्मी नेता को दी अंतरिम सुरक्षा

(जीएनएस)।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भीम आर्मी के नेता को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। यह मामला यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एक FIR से जुड़ा है, जिसमें नेता पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'मूर्खमंत्री' कहने का आरोप लगाया गया।

जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा की बेंच ने आरोपी सुधीर आर्यन को राहत दी। सुधीर आर्यन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 353 (2) [सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान] के तहत मामला दर्ज किया गया था। बेंच ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता (FIR दर्ज कराने वाले) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा।

FIR के अनुसार, आरोपी याचिकाकर्ता भीम आर्मी भारत एकता मिशन (बरेली मंडल) का मंडल उपाध्यक्ष है। उस पर (पहले ळ्द्व३३ी१) पर यह पोस्ट करने का आरोप है: "माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं या मूर्खमंत्री हैं?"

यह टिप्पणी उसने मुख्यमंत्री के उस बयान के संदर्भ में की थी, जिसमें

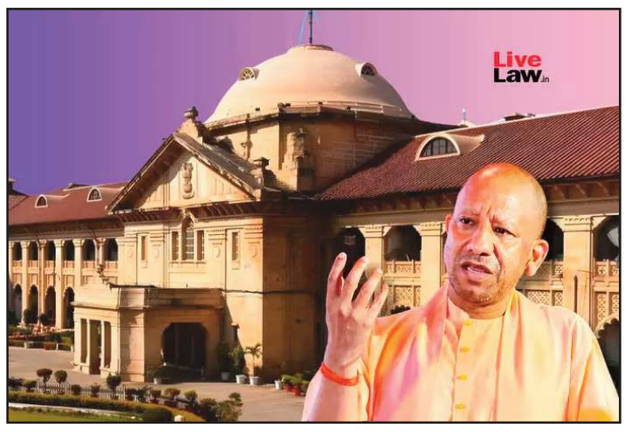

उन्होंने जनता को सलाह दी थी कि वे डीजल और पेट्रोल तभी खरीदें जब उन्हें इसकी जरूरत हो।

FIR रद्द करने की मांग करते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया। उसके वकील ने दलील दी कि अगर FIR में लगाए गए आरोपों को हूबहू मान भी लिया जाए तो भी यह साफ है कि याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री के चरित्र पर कोई लांछन नहीं लगाया।

वकील ने आगे कहा कि आरोपी ने केवल एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, जो मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति को दशार्ता है। ऐसा करके उसने केवल अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग किया है।

इन्हीं आधारों पर वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 505 / इठर की धारा 353(2) के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से पेश AGA ने इस रिट याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें एक संज्ञेय अपराध (गंभीर अपराध) साफ तौर पर बनता है। हालांकि, वह आरोपी के वकील द्वारा पेश की गई तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों को काट नहीं पाए। इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, और साथ ही आरोपी के वकील की दलीलों पर विचार करते हुए बेंच ने एक अंतरिम उपाय के तौर पर निर्देश दिया कि अगले आदेश तक इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब इस मामले को 12 अगस्त को सुनवाई के लिए उचित बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया। इसके साथ ही प्रतिवादियों को अपने-अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए 6 हफ़्तों का समय दिया गया।

पीएम पर अभद्र टिप्पणी विक्षिप्त या पागलपन में रहने वाला कर सकता है, राहुल गांधी के परिवार के पापों को देश की जनता ने भुगताः संतोष पाण्डेय

बीजेपी सांसद ने कहा, राहुल गांधी तो सर्जिकल स्ट्राइक तक पर सवाल खड़े करते हैं. देश विरोधियों के साथ कड़े होते हैं.

(जीएनएस)।

रायपुरः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पाण्डेय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया है. संतोष पांडेय ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जो अभद्र टिप्पणी की है, क्या इण्डियन नेशनल कांग्रेस और उसके नेता इसका उत्तर देंगे? सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि ऐसी टिप्पणी कोई विक्षिप्त व्यक्ति या पागलपन जिस पर सवार है, वही व्यक्ति ही इस प्रकार की टिप्पणी कर सकता है.

राहुल गांधी के बयान की निंदा

भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाण्डेय ने कहा, "बस्तर के अंदर के नक्सल समर्थक और सलवा जुडूम के विरोध में निर्णय देने वाले बी. सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी कांग्रेस बनाती है. 172 जवानों की जिस हिड़मा ने हत्या की, उसके समर्थन में इण्डिया गेट पर नारे लगाए

गए कि 'कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा', उसके चित्र को अपने ट्विटर हैण्डल से ट्वीट करने वाले राहुल गांधी क्या सेना का मनोबल नहीं गिरा रहे हैं? क्या नक्सलियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं? एण्डरसन को देश से भगाने वाली कौन-सी पार्टी है? क्वात्रोच्चि को इस देश से भगाने वाले क्या इण्डियन नेशनल कांग्रेस के लोग नहीं हैं?"

गांधी परिवार के फैसलों पर उठाए सवाल

संतोष पाण्डेय ने कहा, "सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करने वाले राहुल गांधी आज किस मुंह से प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं? साल 2010 में ओड़िशा में नक्सल लीडर के साथ मंच साझा करने राहुल गांधी ओड़िशा पहुंचे थे. भारत जोड़ो यात्रा में नक्सलियों का साथ लेने वाले राहुल गांधी बताएं कि नंदिनी सुन्दर को साल 2011 में स्वतंत्र करने का काम किसने किया? एनएसई में प्रधानमंत्री के ऊपर परिषद का गठन करके उसमें हर्षमंदर से लेकर अनेक राष्ट्रविरोधियों को रखने वाली वह कौन-सी पार्टी है? देश की आत्मनिर्भरता के लिए, स्थिरता के लिए, देश को वैश्विक अर्थशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, आज राहुल गांधी उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं."

चीन और पाकिस्तान का उदाहरण देकर कोसा

भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, "जवाहर लाल नेहरू ने 38 हजार वर्ग किमी भारत की जमीन 1962 में चीन के साथ युद्ध में चीन को दे दी. तब नेहरू ने कहा था कि उस भू भाग में एक घास का तिनका भी नहीं उगता, बंजर जमीन को छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका उत्तर महावीर त्यागी ने यह कहकर दिया था कि यदि मेरे सिर में बाल नहीं है तो सिर या धड़ काटकर चीन को दे दें? 1961 में पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण में पाकिस्तान ने भारत की कितनी जमीन कब्जा कर ली? 1947 में 13 हजार वर्ग किमी का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में नेहरू ने छोड़ दिया जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है." संतोष पाण्डेय ने कहा कि राहुल गांधी के परदादा से लेकर उसकी माता सोनिया गांधी तक राष्ट्र विरोधी प्रकरण, जिनका का कोई प्रायश्चित कर नहीं हो सकता, के पापों को भारत की जनता भुगत रही.

यूपी के लोगों को एक और सुविधा देगी योगी सरकार, 77.93 करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे आग बुझाने वाले 81 वाहन

(जीएनएस)।

लखनऊ। राज्य सरकार ने अग्निशमन व आपात सेवा को दुरुस्त करने के लिए 77.93 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से अग्निशमन (दमकल) विभाग के लिए पांच हजार व ढाई हजार लीटर की क्षमता वाले 81 वाटर टेंडर, 13 फोम टेंडर, 57 महिंद्रा नियो गाड़ियां, 18 वाटर बाउजर व 30 स्मोक एग्जास्टर व ब्लोअर तथा एक डीलक्स बस खरीदी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 325 अग्निशमन केंद्र हैं। इन अग्निशमन केंद्रों में आग बुझाने वाले 1752 वाहन और 2,97,342 उपकरण उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर तहसील पर कम से कम एक-एक अग्निशमन केंद्र स्थापित करने के निर्देश अग्निशमन विभाग को दिए हैं।

इसके बाद से अग्निशमन विभाग नए केंद्र खोलने और रिस्पांस समय को कम करने का प्रयास कर रहा है। राज्य में पहले आग लगने पर रिस्पांस समय 20 से 25 मिनट का था, जिसे अब 10 से 15 मिनट कर लिया गया था। अग्निशमन विभाग रिस्पांस समय को और कम करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए नए वाहनों व उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

फिलहाल शासन ने 6.74 करोड़ रुपये की लागत से नौ बड़े वाटर टेंडर, 30 स्मोक एग्जास्टर व ब्लोअर की खरीद को स्वीकृति दी है। इसके अलावा 10.19 करोड़ रुपये से पांच हजार लीटर की क्षमता वाले 13 फोम टेंडर, 32.85 करोड़ रुपये से 53 छोटे वाटर टेंडर, 39.56 लाख रुपये से एक डीलक्स बस, 5.38 करोड़ रुपये से 57 महिंद्रा नियो गाड़ियां, 18.55 करोड़ रुपये से 18 वाटर ब्राउजर व 3.81 करोड़ रुपये से 2500 लीटर की क्षमता वाले 16 वाटर टेंडर खरीदे जाएंगे। अग्निशमन विभाग की कोशिश है कि रिस्पांस समय को कम करके पांच से आठ मिनट कर लिया जाए।

योगी सरकार का बड़ा प्लान? शिक्षामित्रों को जल्द मिल सकता है नया तोहफा

(जीएनएस)।

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों और पार्ट टाइम अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी. जाने कब से लागू माना जाएगा यह मानदेय. इसके अलावा इन्हें एक और गिफ्ट मिल सकता है?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षामित्रों और पार्ट टाइम अनुदेशकों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

सरकार के इस फैसले से लाखों शिक्षा कर्मियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. साथ ही आने वाले समय में इनकी सेवा अवधि को लेकर भी अपडेट आ सकता है.

सरकार के इस फैसले से लाखों शिक्षा कर्मियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. साथ ही आने वाले समय में इनकी सेवा अवधि को लेकर भी अपडेट आ सकता है.

योगी सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय में बड़ा इजाफा किया है. पहले शिक्षामित्रों को हर महीने 10,000 रुपये मानदेय दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है.लंबे समय से शिक्षामित्र संगठन मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया.

योगी सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय में बड़ा इजाफा किया है. पहले शिक्षामित्रों को हर महीने

10,000 रुपये मानदेय दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है.लंबे समय से शिक्षामित्र संगठन मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया.

सरकार ने पार्ट टाइम अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है.पहले अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है.इस फैसले से हजारों अनुदेशकों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा. सरकार ने पार्ट टाइम अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है.पहले अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है.इस फैसले से हजारों अनुदेशकों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा.यानी संबंधित कर्मचारियों को अप्रैल महीने से नई दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा.यानी संबंधित कर्मचारियों को अप्रैल महीने से नई दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा. विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब शिक्षामित्रों की सेवा अवधि बढ़ाने का मुद्दा भी फिर से चर्चा में है. इसके बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है. विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब शिक्षामित्रों की सेवा अवधि बढ़ाने का मुद्दा भी फिर से चर्चा में है.

इसके बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि इस फैसले से शिक्षा कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. सरकार लगातार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि इस फैसले से शिक्षा कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. सरकार लगातार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है.

भारत में 10 दिन में 3 बार बढ़े दाम, तो पाकिस्तान में क्यों सस्ता हो रहा पेट्रोल?

(जीएनएस)।

भारत में पिछले 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं, वहीं पड़ोसी ढ्ढ२३ल्ल ने एक बार फिर ईंधन की कीमतों में कटौती कर दी है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल 6 रुपये और डीजल 6.80 रुपये प्रति लीटर सस्ता किया है। ऐसे समय में जब ईरान-अमेरिका तनाव और कच्चे तेल की कीमतों का दबाव पूरी दुनिया पर है, तब पाकिस्तान में दाम कम होना चर्चा का विषय बन गया है।

दूसरी तरफ भारत में लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों की चिंता बढ़ रही है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान कीमतें कैसे घटा पा रहा है जबकि भारत में दाम बढ़ रहे हैं।

पाकिस्तान में लगातार दूसरी बार राहत

पाकिस्तान ने लगातार दूसरे हफ्ते पेट्रोल-डीजल के दाम घटाए हैं। नई कीमतों के मुताबिक वहां पेट्रोल 403.78 पाकिस्तानी रुपये और हाई स्पीड डीजल 402.78 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पिछले हफ्ते भी सरकार ने करीब 5 रुपये की कटौती की थी। पाकिस्तान में सरकार हर शुक्रवार ईंधन की कीमतों की समीक्षा कर रही है। वहां तेल कीमतों में तेजी से बदलाव हो रहा है क्योंकि सरकार

अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू दबाव दोनों को ध्यान में रखकर फैसला ले रही है।

पहले पाकिस्तान में भी हुई थी भारी बढ़ोतरी

हालांकि अभी कीमतें घट रही हैं, लेकिन कुछ महीने पहले पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल रिकॉर्ड स्तर तक महंगे हो गए थे। ईरान-अमेरिका और इजरायल तनाव बढ़ने के बाद मार्च में वहां पेट्रोल-डीजल 55 रुपये प्रति लीटर तक महंगा किया गया था। अप्रैल में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई थी। यानी पाकिस्तान पहले कीमतें तेजी से बढ़ा चुका है और अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में थोड़ी राहत मिलने पर दाम कम कर रहा है। इसके बावजूद वहां ईंधन अभी भी काफी महंगा बना हुआ है।

भारत में क्यों बढ़ रहे हैं दाम

क्ल्र्ं में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक तनाव का असर सीधे ईंधन कीमतों पर दिख रहा है। पिछले 10 दिनों में तीन बार पेट्रोल-डीजल महंगा किया गया है। शनिवार को भी पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। इसके अलावा सीएनजी के दाम में भी इजाफा हुआ। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए होर्मुज स्ट्रेट और मिडिल ईस्ट तनाव जैसी घटनाओं का असर यहां जल्दी दिखता है।

आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है

पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खाने-पीने के सामान, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में लोग महंगाई से परेशान हैं। पाकिस्तान में राहत मिलने से वहां आम लोगों को थोड़ी मदद मिल सकती है, जबकि भारत में लगातार बढ़ती कीमतें मिडिल क्लास और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर दबाव बढ़ा रही हैं। आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दाम तय करेंगे कि राहत मिलेगी या महंगाई और बढ़ेगी।

सीएम योगी ने दिए 17 कंपनियों को आवंटन पत्र, यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र बनेगा उद्योगों का नया हब

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार देश के सबसे बड़े औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है. इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने 17 बड़ी कंपनियों को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में आवंटन पत्र प्रदान किए. इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 12 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है. खास बात यह है कि अधिकांश कंपनियों ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई है. इन परियोजनाओं से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक उद्योगों का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है.

सोलर और हरित ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश सीईएससी ग्रीन पावर लि. द्वारा किया जा रहा है.आरपी-संजीव गोयनका समूह की यह कंपनी 100 एकड़ क्षेत्र में 3 गीगावाट क्षमता की सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई स्थापित करेगी. इस परियोजना में ₹3805 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा. वहीं इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्रा. लि. 25 एकड़ क्षेत्र में 4 गीगावाट क्षमता की सोलर पीवी सेल निर्माण इकाई स्थापित करेगी. इस परियोजना में ₹1146 करोड़ का निवेश होगा और 500 रोजगार सृजित होंगे. इन दोनों परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश हरित ऊर्जा निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में तेजी से उभरता दिखाई दे रहा है.

सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा सेक्टर को नई ताकत

सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीईएस क्षेत्र में भी बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं. आर्सेनल इन्फोसॉल्यूशंस प्रा. लि. ₹71.19 करोड़ निवेश कर आईटी/आईटीईएस इकाई स्थापित करेगी, जिससे 1140 रोजगार सृजित होंगे. कंपनी ने 40 प्रतिशत स्थानीय रोजगार देने की बात कही है. वर्चुअल एंप्लॉयी प्रा. लि. ₹48 करोड़ निवेश कर आईटी/आईटीईएस परियोजना स्थापित करेगी, जिससे 600 लोगों को रोजगार मिलेगा. इसमें 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह एमड्यूस इंडिया प्रा. लि. ₹160 करोड़ की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना स्थापित करेगी, जिससे 275 रोजगार सृजित होंगे. क्वार्क्स टेक्नॉसॉफ्ट प्रा. लि. डाटा प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करेगी. कंपनी इसके लिए ₹47.47 करोड़ निवेश कर लगभग 1800 युवाओं को रोजगार देगी. इससे प्रदेश में डाटा और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी.

इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी

साइनाथ सेल्स एंड सर्विसेज प्रा. लि. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण इकाई स्थापित करेगी. कंपनी इसमें ₹37.19 करोड़ निवेश कर 300 लोगों को रोजगार देगी. इसी तरह, समरकूल होम एप्लायंसेज लि. इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माण क्षेत्र में ₹46.13 करोड़ निवेश करेगी और 532 रोजगार उपलब्ध कराएगी. एंजिलिटी इलेक्ट्रोटेक्निक्स प्रा. लि. इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स रिले निर्माण क्षेत्र में ₹35 करोड़ निवेश करेगी, जिससे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा. अल्फा कम्युनिकेशन एलएलपी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और वायर निर्माण क्षेत्र में ₹42.59 करोड़ निवेश कर 150 रोजगार सृजित करेगी. एडवांस पैनल्स एंड स्विचगियर्स प्रा. लि. पावर ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और ईवी चार्जर निर्माण क्षेत्र में ₹66 करोड़ का निवेश करेगी. इससे 200 लोगों को रोजगार मिलेगा. वेगा इंडस्ट्रीज प्रा. लि. घरेलू उपकरण, पर्सनल केयर उपकरण और इलेक्ट्रिकल उत्पाद निर्माण क्षेत्र में ₹91 करोड़ निवेश करेगी तथा 500 रोजगार उपलब्ध कराएगी.

रेलवे, वस्त्र और पैकेजिंग उद्योग को भी बढ़ावा

जेएमवी एलपीएस लि. रेलवे सिग्नलिंग उत्पाद निर्माण इकाई स्थापित करेगी। ₹54.80 करोड़ की इस परियोजना से 405 लोगों को रोजगार मिलेगा और 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साहू इंटरनेशनल अटायर प्रा. लि. रेडीमेड वस्त्र निर्माण इकाई स्थापित करेगी। ₹70 करोड़ की इस परियोजना से 1992 रोजगार सृजित होंगे। इसमें 70 प्रतिशत स्थानीय रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। ऋद्धि सिद्धि पेपर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोरोगेटेड बॉक्स निर्माण परियोजना स्थापित करेगी। ₹59.09 करोड़ की इस परियोजना से 172 लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी ने 85 प्रतिशत स्थानीय रोजगार देने की प्रतिबद्धता जताई है.

स्मार्ट ऊर्जा और आधुनिक तकनीक पर फोकस

एनडीएसबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. स्मार्ट एनर्जी मीटर और डाटा एनालिसिस परियोजना स्थापित करेगी। ₹40.52 करोड़ की इस परियोजना से 217 लोगों को रोजगार मिलेगा. इसमें 90 प्रतिशत स्थानीय रोजगार का प्रावधान रखा गया है। एमएए पेट प्रा. लि. हाई बैरियर एआई आधारित पीईटी शीट निर्माण इकाई स्थापित करेगी। ₹29.84 करोड़ की इस परियोजना से 68 लोगों को रोजगार मिलेगा.

उत्तर प्रदेश में लागू होगी बाल श्रमिक विद्या योजना, कामगार बच्चों को पढ़ायेगी योगी आदित्यनाथ सरकार

(जीएनएस)।

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के सभी बाल श्रमिकों को शिक्षित करेगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इसमें तय किया गया कि सभी लेबर अड्डों को सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिक विद्या योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी। अभी यह योजना 20 जिलों में चल रही है। जिसमें आठ से 18 वर्ष के कामगार बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाकर उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही औद्योगिक शहरों के लेबर अड्डे श्रमिक सुविधा केंद्र के रूप में विकसित होंगे। श्रमिकों के लिये सुरक्षित आवास व्यवस्था होगी। सरकार ने राज्य के कामगारों के लिये जर्मनी, जापान और स्लोवाक गणराज्य में रोजगार की संभावनायें तलाशी हैं, इसके लिए युवकों को अंग्रेजी सहित इन देशों का भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के 75 जिलों में चलाने, 'सेवामित्र व्यवस्था' और प्रभावी बनाने, रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि श्रमिक सिर्फ उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की शक्ति हैं। यह भी कहा कि कोई बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाकर बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जाये। उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो। ऐसे बच्चो को निजी क्षेत्र के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण दिया जाये।

मुख्यमंत्री ने 'सेवामित्र व्यवस्था' को जनसुविधा का मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्थाएं कामगारों के लिए नये अवसर पैदा करती हैं। आवश्यकता के अनुसार सरकारी विभागों में सेवामित्र व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाये।

इस बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 से संचालित इस व्यवस्था के तहत नागरिक मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, कॉल सेंटर के माध्यम से नागरिक घरेलू सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर 1097 सेवा प्रदाता, 5049 सेवामित्र और 54,747 कुशल कामगार पंजीकृत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी उद्योगों के अनुकूल और श्रमिक हितों के बीच संतुलन वाला वातावरण बनायें। सरकार की यही नीति है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 32,583 कारखाने पंजीकृत हैं। मार्च 2017 में यह संख्या 14,176 थी। यानी अप्रैल 2017 के बाद 18,407 नए कारखानों का पंजीकरण हुआ है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियो से कहा कि निर्माण श्रमिकों के लिए औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित 'लेबर अड्डों' को श्रमिकों के एकत्रीकरण स्थल के रूप में नहीं, बल्कि श्रमिक सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाये। क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया जाये।

मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्रस्तावित औद्योगिक श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास योजना को तेजी से पूरा कराने का का निर्देश दिया। कानपुर के विष्णुपुरी में 200 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है। जहां कारपेंटरी, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लंबर, पेंटर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सहित विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बेनाझाबर में 200 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला छात्रावास प्रस्तावित है।